भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1425

29.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

तेलंगाना में इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के लिए समर्थन

1425 **डॉ. कडियम काव्य:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत 2,800 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए तेलंगाना से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या राज्य ने हाइब्रिड जीसीसी मॉडल अपनाने की अनुमति का अनुरोध किया है, जहाँ बसें ओईएम द्वारा प्रदान की जाती हैं, लेकिन मौजूदा रोज़गार की सुरक्षा के लिए टीजीएसआरटीसी कर्मचारियों द्वारा उनका संचालन और रखरखाव किया जाता है;

(ग) क्या मंत्रालय राष्ट्रीय ईवी प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदन हेतु इस रोज़गार-संरक्षण मॉडल पर विचार कर रहा है; और

(घ) क्या सरकार ईवी रेट्रो-फिटमेंट पहलों के लिए समर्थन बढ़ाने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए टीजीएसआरटीसी को भुगतान सुरक्षा तंत्र तक पहुंच की अनुमति देने का विचार है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) जी हां, सरकार को पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत तेलंगाना से 2,800 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख)और (ग): पीएम ई-ड्राइव के तहत, ई-बसों के लिए सहायता राज्य/शहर परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के माध्यम से परिचालन व्यय (ओपेक्स)/सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल पर प्रदान की जाएगी। सीईएसएल द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एकत्रीकरण मॉडल पर ई-बसों की खरीद की जाएगी। तेलंगाना राज्य ने हाइब्रिड जीसीसी मॉडल की खोज करने की अपनी मंशा व्यक्त की है। हालाँकि, वर्तमान में पीएम ई-ड्राइव स्कीम के मौजूदा ढांचे के तहत इस मॉडल पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) ईवी रेट्रो-फिटमेंट को पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, इसलिए भुगतान सुरक्षा तंत्र तक पहुंच का प्रश्न ही नहीं उठता।

****